



राहत, पारदर्शिता और नए वादों का बजट

यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में देश की आबादी का एक छोटा हिस्सा छया हुआ है। चर्चा का विषय देश के करीब 4.3 करोड़ आयकरदाताओं को मिली कर राहत है। वित्त मंत्री ने उन्हें कुल 1 लाख करोड़ रुपये की राहत दी है, जो केंद्र के कर राजस्व की करीब 2.5 फीसदी बैठती है। एक ही बार में इतनी बड़ी आयकर राहत इस देश में पहले कभी नहीं दी गई है, इसलिए इसकी चर्चा होनी लाजिमी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लगातार सातवें पूर्ण बजट में अलग-अलग आय वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर की दरें ही नहीं घटाई गईं बल्कि मध्य वर्ग को कई दूसरी राहत भी दी गईं। खेत पर कर कटौती (टीडीएस) के लिए आसान नियम भी इसमें शामिल हैं, जिनसे करदाताओं पर बोझ घटेगा। ये कदम देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती देखकर उठाए गए हैं ताकि कर घटने से खपत बढ़े और वृद्धि भी पटरी पर लौटे। यह तो समय ही बताएगा कि छोटी सी आबादी को आयकर में दी गई भारी छूट से खपत कितनी बढ़ी और मांग तथा वृद्धि में कितना इजाफा हुआ। किंतु यह बजट आयकर में राहत देने तक ही नहीं सिमटा है। देश-विदेश से आ रही चुनौतियों के बीच वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के वित्तीय संसाधनों को जैसे संभाला और इस्तेमाल किया है वह सराहनीय है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर सरकार ने लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो मार्क की बात है। संशोधित अनुमानों में सरकार का शुद्ध राजस्व बजट अनुमान से 1.3 फीसदी कम हो गया। व्यक्तिगत आयकर संग्रह तेजी से बढ़ा मगर कॉरपोरेशन कर तथा गैर कर प्राप्ति कम होने से संग्रह कम रह गया। इसकी भरपाई व्यय में 2 फीसदी कटौती से हो गई, जो पूंजीगत व्यय में 8 फीसदी कमी का नतीजा थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि व्यय की गुणवत्ता कई साल बाद बिगड़ी है मगर राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.8 फीसदी पर रोक लिया गया, जिसके लिए पिछले बजट में 4.9 फीसदी का अनुमान लगाया गया था।

shivdayalmishra@gmail.com

मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय: उभरती युवा प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए नई युवा नीति का अनुमोदन प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए 3 नई नीतियां अनुमोदित

वाइस-चांसलर्स को कुलगुरु की पदवी देने के लिए आएका विधेयक

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में मंत्रिमण्डल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के लिए राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिस्ती, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिस्ती एवं राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिस्ती लाने, युवाओं को सक्षम एवं सशक्त बनाकर विकसित राजस्थान के संकल्प की सिद्धि के लिए नई युवा नीति के अनुमोदन, विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर्स को कुलगुरु की पदवी प्रदान करने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटीज लॉज (अमेण्डमेंट) बिल लाने, रीको औद्योगिक



क्षेत्रों के विकास को गति देने के उद्देश्य से राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (अमेण्डमेंट वैलिटेशन) बिल लाने सहित कार्मिक कल्याण और सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए।

प्रदेश को ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब बनाने के लिए टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिस्ती-2025

मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल एवं पीएचडी मंत्री कन्हैया लाल ने बताया कि राज्य सरकार वस्त्र व परिधान के क्षेत्र में प्रदेश को ग्लोबल मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहती है। इसे ध्यान में रखते हुए मंगलवार को कैबिनेट में मंजूरी की गई राजस्थान टैक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिस्ती-2025 प्रदेश में टैक्सटाइल एण्ड अपैरल क्षेत्र के सतत व समग्र विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में रोजगार सृजन, कौशल विकास, नवाचार, उत्पादकता और निर्यात को बढ़ावा देगी। वहीं दूसरी ओर इससे वैश्विक स्तर पर स्थानीय वस्त्र उत्पादकों की दक्षता और विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। इस नीति से प्रदेश के वस्त्र उत्पादक लाभान्वित होंगे और राज्य में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के संभावित निवेश से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

डेटा सेंटर पॉलिस्ती-2025 से विकसित होगा विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम

पटेल ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में लिजी क्षेत्र में डेटा सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिस्ती-2025 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस पॉलिस्ती का उद्देश्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर इकोसिस्टम विकसित करना है एवं राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाना है। यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटरों की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावित बनायेगी। इस नीति में डेटा सेंटर सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए एसेट टैक्स इन्सुलेशन, सनराइज इन्सुलेशन, ब्याज अनुदान, बैंकिंग, ट्रांसमिशन व व्हीलिंग शुल्क में छूट, भूमि संबंधी फ्लेक्सिबल भूगलान सुविधा, स्टॉप इयूटी, भू-स्वांतरण व विद्युत शुल्क में छूट तथा बाह्य विकास शुल्क से छूट सहित कई प्रवधान किए गए हैं।

पीएम मोदी आज महाकुंभ में लगाएंगे डुबकी

नई दिल्ली @ जागरूक जनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को महाकुंभ आएंगे। वह सुबह करीब 10.30 बजे महाकुंभ पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ भूतान के नरेश भी मौजूद रहेंगे। नये प्रोटोकाल के मुताबिक, पीएम मोदी सुबह करीब 10.30 बजे बमरोली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहां से डीपीएस हेलीपैड जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी यहां से निषादराज क्रूज से वीआईपी घाट पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी संगम स्नान के बाद गंगा आरती और पूजन करेंगे।



उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी रही भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के दौरे पर

भगवान श्री देवनारायण ने सर्व समाज व सनातन की रक्षा हेतु विभिन्न कार्य किए

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भीलवाड़ा जिले के आसींद क्षेत्र के दौरे पर रही। उप मुख्यमंत्री ने सर्वाभोज में भगवान श्री देवनारायण जी के 1113वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उपमुख्यमंत्री ने देवनारायण जी के मंदिर दर्शन के पश्चात मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री देवनारायण ने समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने का कार्य किया। भगवान श्री देवनारायण ने सर्व



समाज व सनातन की रक्षा हेतु विभिन्न कार्य किये। साथ ही, उपमुख्यमंत्री ने भगवान श्री देवनारायण जयंती के अवसर पर उपस्थित आमजन को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधि व आमजन की मांग पर उपमुख्यमंत्री ने प्रेमसागर सरोवर के सौंदर्यीकरण व लाइट डेकोरेशन के कार्य व देवनारायण आवासीय बालिका विद्यालय खोलने की घोषणा की।

HBOT जीवन रक्षक प्रणाली द्वारा इलाज ऑक्सीजन (प्राणवायु) ट्रीटमेंट

- » मस्तिष्क चोट, पक्षाघात/लकवा
- » सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म
- » असाध्य घाव/शुगर के घाव
- » कैंसर (रेडियो थेरेपी) के साईड इफेक्ट
- » अचानक बहरापन (Hearing Loss)
- » डाईबेटिक फुट में अम्पुटेशन (पैर कटने) से बचाव

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:-
98290-17133, 70737-77133
9983317133
डॉ. हिमांशु अग्रवाल M.B.B.S. M.D.
नेशनल हायपरबैरिक रिसेच सेंटर
594-B-C, जेम्स कॉलोनी, सैक्टर-3, मंदिर मोड, विद्याधर नगर, जयपुर
Dept. of Hyperbaric Medicine
Fortis Escorts Hospital
JLN Marg, Malviya Nagar, Jaipur
E-mail : hbotjaipur@gmail.com
www.nationalhbot.in

asianpaints

ग्राफ़िन बनाता है जहाज़ों को वाटरप्रूफ़, और अब आपके पेन्ट को भी।

APEX ULTIMA PROTEK

LAMINATION GUARD

Powered By GRAPHENE

12 YEARS WARRANTY*

POWERED BY GRAPHENE

12 YEARS WARRANTY*

APEX ULTIMA PROTEK

*12 साल की वॉरंटी शेड के भूगर्भ होने और फिल्म की सन्नद्धता पर लागू। कृपया एशियन पेंट्स एपेक्स अल्टिमा प्रोटेक कंटीन्यूअसली www.asianpaints.com पर देखें।

SCAN TO WATCH GRAPHENE IN ACTION

कहीं आप गलत तेल के शिकार तो नहीं हो रहे हैं ?

देखी दिल के लिये, दादी वाला देखी तेल...

Kabira[®] Healthy Growth Yellow Mustard Oil

स्वदेशी पीली सरसों का तेल है, प्राचीन, पोषिक एवं परम्परा।

- ▶ प्राचीन शीलत विधी घाणों से निर्मित।
- ▶ निर्माण विधी उच्च ताप रहित।
- ▶ निर्माण में कोई रासायनिक प्रयोग नहीं।
- ▶ केन्सर को रोकने में लाभदायक।*
- ▶ मधुमेह को नियंत्रित करने में लाभदायक।
- ▶ एसीडीटी एवं गैस्ट्रिक रोगों में मददगार।
- ▶ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में लाभदायक।
- ▶ केवल देसी सरसों द्वारा निर्मित।
- ▶ मोटापा घटाने में लाभदायक।
- ▶ बालों के लिए एक उत्तम तेल।
- ▶ ओमेगा 3 एवं ओमेगा 6 से भरपूर।
- ▶ तीखी गंध रहित होने के कारण सभी व्यंजनों में उपयोगी।
- ▶ अनेक औषधीय गुणों से भरपूर।
- ▶ सभी तेलों के मुकामले सबसे कम सेच्युरेटेड फेट्स।*
- ▶ छः हजार वर्षों से मानव के लिए उपयोगी।

Kabira Cold Pressed Oils are Also Available in :
Kachchi Ghani Mustard Oil (Pungent Smell)
Kachchi Ghani Groundnut Oil | Kachchi Ghani Sesame (Til) Oil

स्वस्थ जीवन के लिए कोनसा तेल उपयोग करें ?

तेल आप उपयोग करें	तेल आप उपयोग ना करें
कबीरा पीली सरसों का तेल	कबीरा रिफाईण्ड पामोलीन तेल
कबीरा कच्ची घानी सरसों का तेल	कबीरा रिफाईण्ड राईस ब्रान तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल	कबीरा ब्लेंडेड एवं कानोला तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड तिल्ली का तेल	कबीरा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल
कबीरा कोल्ड प्रेस्ड बादाम तेल	कबीरा रिफाईण्ड सूरजमुखी तेल
	कबीरा रिफाईण्ड मूंगफली तेल

कबीरा पीली सरसों तेल को फोवर्टी मूल्य में लेने के लिए इस विज्ञापन एवं अपनी डिटेल्स को 90017-99117 पर कॉल करने पर और फ्री में लाइफ़ मेम्बर बनने एवं पाएँ 590 रु. की चांदी की फ्री एवं कोनवास वेग बिलकूल Free ONLY FOR NEW MEMBER, LIMITED TIME OFFER

समय ब्रत एवं उपास में उपयोगी	केवल कबीरा कोल्ड प्रेस्ड मूंगफली का तेल
सर्दियों में उपयोगी	कबीरा कोल्ड प्रेस्ड तिल्ली का तेल
हर मौसम में उपयोगी	कबीरा पीली सरसों एवं कच्ची घानी सरसों तेल
दियावली, दिपक प्रज्वलन के लिए	कबीरा तिल्ली एवं कच्ची घानी सरसों तेल

Manishankar Oils Pvt Ltd

TO Open Kabira Hand Made Exclusive Store or Other Trade Inquiries Please Contact : +91 98290 50738

ALSO DEALS IN KISAN, PEKURA, TILAK, HANDMADE, MURARKA, BANSI, KABIRA COLD PRESSED (EDIBLE OIL, SPICES & TEA)

*GOVERNMENT OF INDIA'S NATIONAL AWARDED *GOVERNMENT OF RAJASTHAN'S UDYOG RATAN AWARDED

पंचांग

ज्योतिर्विद अक्षय शास्त्री

संकेत पंचांग, अनंतराष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता

जागरूक जनता पंचांग, नक्षत्र, तिथि, चौघड़िया

सूर्योदय-सूर्यास्त, तिथि

बुधवार, 05/02/2025

सूर्योदय : 07:14 सूर्यास्त : 18:07 चन्द्रोदय : 11:29 चन्द्रास्त : 00:24 शक सम्वत : 1946 कौथी अमान्ता महाना : माघ पूर्णिमांत : माघ सूर्य राशि : मकर चन्द्र राशि : मेष पक्ष : शुक्ल तिथि : अष्टमी, 24:37 तक वार : बुधवार शक सम्वत : 1946 कौथी गुजराती सम्वत : 2081 नल चन्द्रमास माघ : पूर्णिमांत प्रविष्ट/गते : 23 माघ : अमान्त

नक्षत्र, योग, करण

नक्षत्र : भरणी, 20:34 तक प्रथम करण : विष्ट, 13:33 तक
योग : शुक्ला, 21:13 तक द्वितीय करण : बावा, 24:37 तक

शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त 05:22 एम से
प्रातः सन्ध्या 05:48 एम से
विजय मुहूर्त 02:25 पी एम से
गोधूलि मुहूर्त 06:01 पी एम से
सायाह सन्ध्या 06:04 पी एम से
अमृत काल 04:00 पी एम से
निशिता मुहूर्त 12:09 एम, फरवरी 6 से
सर्वाय सिद्धि योग 08:33 पी एम से
रवि योग 08:33 पी एम से

निवास और शूल

दिशा शूल : उत्तर में
रह काल वास दक्षिण-पश्चिम में
होमाहुति : शुक्र
कुंभ चक्र: दक्षिण

चौघड़िया

दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
लाभ : 07:13 - 08:34	उद्वेग : 18:07 - 19:45
अमृत : 08:34 - 09:56	शुभ : 19:45 - 21:23
काल काल वेला : 09:56 - 11:18	अमृत : 21:23 - 23:01
शुभ : 11:18 - 12:40	चर : 23:01 - 00:39
राज वार वेला : 12:40 - 14:01	रोग : 00:39 - 02:18
उद्वेग : 14:01 - 15:23	काल : 02:18 - 03:56
चर : 15:23 - 16:45	लाभ : 03:56 - 05:34
लाभ : 16:45 - 18:07	उद्वेग : 05:34 - 07:12

अमृत, शुभ, लाभ और चर को शुभ चौघड़िया माना जाता है एवं उद्वेग, काल एवं रोग को अशुभ चौघड़िया माना जाता है।

आज अष्टमी

आज कौन सा कार्य करें

अष्टमी : संक्राम, वास्तु, शिल्प, लेखन, स्त्री, रत्न धारण, आभूषण खरीदना व नव अष्टमी को शुभ है।

बुधवार को क्या करें

बुधवार की प्रकृति चर और सौम्य मानी गई है। यह भवनाल गणेश और दुर्गा का दिन है। कमजोर मस्तिष्क वालों को बुधवार के दिन उपवास रखना चाहिए। ये कार्य करें - सूखे सिंदूर का तिलक लगाएं। बुधवार को दुर्गा के मंदिर जाना चाहिए। पूर्व, दक्षिण और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर सकते हैं। इस दिन जमा किराए गए धन में संकलित रहती हैं। मंत्रणा, मंथन और लेखन कार्य के लिए भी यह दिन उपयुक्त है। ज्योतिष, शोध, दलाली जैसे कार्यों के लिए भी यह दिन शुभ माना गया है। यह कार्य न करें- उत्तर, पश्चिम और ईशान में यात्रा न करें। बुधवार को धन का लेन-देन नहीं करना चाहिए। बुधवार को लड़की को माता को सिर नहीं धोना चाहिए, ऐसा करने से लड़की का स्वास्थ्य बिगड़ता है या उसके समक्ष कोई कष्ट आता है।

नोट : शुक्ल पक्ष में एक से पंचमी तक तिथियां अशुभ कही गई हैं, क्योंकि इन तिथियों में चंद्रमा क्षीण बल होता है और चंद्र बल उन दिनों नहीं रहने से कार्य सफल नहीं होते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी से अमावस्या तक तिथियों में चंद्र बल क्षीण होने से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए।

आपणी सड़कों.... अच्छी गुणवत्ता की सड़क निर्माण की सरल हिन्दी भाषा में मिलेंगी जानकारी- उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया पुस्तिका का विमोचन

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार को उपमुख्यमंत्री कार्यालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण की जानकारी हेतु "आपणी सड़कों....एक मात्र संकल्प: गुणवत्तापूर्ण निर्माण" शीर्षक से हिन्दी में तैयार की गई पुस्तिका का विमोचन किया। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च गुणवत्ता की सड़क किसी भी देश/राज्य की अर्थव्यवस्था की धुरी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार का प्राथमिक लक्ष्य बेहतर सड़क नेटवर्क विकसित करने के साथ सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है। उन्होंने कहा कि सरल बोल-चाल की भाषा में तैयार की गई यह पुस्तिका सड़क निर्माण से जुड़े अभियंताओं-सुपरवाइजरों एवं अन्य लोगों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और गुणवत्ता पूर्ण सड़क निर्माण सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध होगी। मुख्य अभियंता (गुण नियंत्रण) जसवंत खत्री ने बताया कि काफी समय से प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य से जुड़े विभागीय



पुस्तिका की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी जिसमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण से संबंधित अखिल भारतीय स्तर के मानकों, सरल निर्माण कार्य विधि एवं अन्य तकनीकी जानकारी सरल बोल-चाल की भाषा में एक साथ प्राप्त की जा सके। उन्होंने बताया कि पोडब्ल्यूडी की क्वालिटी कन्ट्रोल सिकल, बीकानेर के अध्यक्ष अभियंता सुनील गहलोर एवं उनकी टीम द्वारा यह पुस्तिका तैयार की गई है।

पुस्तिका में मिलेगी यह जानकारी

गैर शहरी सड़कों हेतु ज्यामितीय डिजाइन मानक, मिट्टी का कार्य, ग्रेनुलर सब बेस कार्य, बेस कोर्स, डामर कार्य, सीमेंट कंक्रीट कार्य, इन्टरलॉकिंग ब्लॉक कार्य, रिस ड्रेनेज कार्य तथा गुण नियंत्रण सहित विभिन्न उपयोगी जानकारी पुस्तक में समाहित की गई है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, शासन सचिव डी आर मेघवाल, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियंता टी.सी. गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री शर्मा व विधानसभा अध्यक्ष देवनांनी ने विधानसभा में किया नेवा सेवा केन्द्र का शुभारंभ ई-लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर के रूप में कार्य करेगा नेवा सेवा केन्द्र

जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनांनी ने सोमवार को विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र का फीता खोलकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष मदन राठौड़ सहित विधायकगण भी मौजूद थे। देवनांनी ने बताया कि नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के इस केन्द्र से विधान सभा को पेपरलेस बनाये जाने से संबंधित नेवा माड्यूल का प्रशिक्षण और इससे संबंधित तकनीकी सहायता विधायकगण को उपलब्ध कराई जायेगी। यह केन्द्र विधायकगण के साथ अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए भी ई-लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की राज्य की विधान सभाओं को



ई-विधान एप्लीकेशन के उपयोग से राजस्थान विधान सभा का सदन और विधानसभा सचिवालय भी लोकसभा तथा अन्य विधान सभाओं की तर्ज पर डिजिटल हो गये हैं। उन्होंने बताया कि इस ई-विधान एप्लीकेशन से राज्य विधान सभा के सदस्यों और राज्य के अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया प्रतिनिधिगण, अनुसंधानकर्ता और आम नागरिकगण को विधान सभा से संबंधित विधेयक, रिपोर्ट्स, सदन के पटल पर रखे जाने वाले विधेयक, प्रश्न, बुलेटिन सहित अन्य कार्यवाही डिजिटल बनाये जाने के लिए नेवा एप्लीकेशन का संचालन राजस्थान विधानसभा में भी किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष देवनांनी ने बताया कि वन-नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत नेशनल विवरण संबंधित सूचनाओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाये जाने वाली इस महत्वपूर्ण परियोजना की अध्यक्ष देवनांनी ने निरन्तर समीक्षा की है।

शर्मा ज्योतिष गौरव सम्मान से सम्मानित

जयपुर @ जागरूक जनता। वैदिक ज्योतिषी एवं केंपी विशेषज्ञ इंजीनियर कुलदीप शर्मा को वैदिक ज्योतिष के विकास एवं विस्तार के लिए एपेक्स यूनिवर्सिटी के चंसलर प्रोफेसर सोमदेव शताशु, चेयरपर्सन डॉ. रवि ज्योतिष एवं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के संस्थापक डॉ. अनिश व्यास द्वारा एपेक्स यूनिवर्सिटी, सीतापुर, जयपुर परिसर में ज्योतिष गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया।

किलकारी 2025 के तहत उत्साह से मनाई बसंत पंचमी

जयपुर @ जागरूक जनता। "कितानो का साथ हो, पेन पर हाथ हो, काफिया आपके पास हो, पढाई दिन रात हो, जिनकी के हर इन्तिहान में आप पास हो। ऐसी शक्ति दाता विद्या दायिनी वीणा वादनि श्वेत वस्त्र धारणी माँ सरस्वती भगवती देवी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर जैन कॉन्वेंट स्कूल में सरस्वती माता के जन्मदिवस के साथ वाषिष्ठीकोत्सव का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के समक्ष विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता जैन ने दीप प्रज्वलित किया। वाषिष्ठीकोत्सव का शीर्षक "किलकारी" रखा गया। उन्होंने बताया कि बचपन गीली माटी के समान होता है। इस माटी में जैसा बीज बोया जाता है ठीक वैसा ही फल आपके पास होता है। इसके पश्चात छात्रों कि शानदार प्रस्तुति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माँ सरस्वती इन सभी बच्चों में समा गईं हो। इसके पश्चात सभी बच्चों ने भोजन किया। अगले दिन सूर्य सप्तमी पर सभी बच्चों को योग टीचर अनिल जैन ने सूर्य देव के समक्ष सूर्य नमस्कार कराया।

राशिफल

माघ, शुक्ल, अष्टमी, 2081 बुधवार, 05 फरवरी - 11 फरवरी, 2025

मेष चू, चे, चो, ला, ली, लु, ले, ली, अ

लम्बित मामलों के परिणाम आपके पक्ष में होने की सम्भावना है। व्यवसाय में सहयोगी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे। निर्माण कार्यों में आपका सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकते हैं।

वृषभ ई,उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो

व्यापार में जिम्मेदारियों बढ़ सकती हैं। आपकी कर्तव्यनिष्ठा की प्रशंसा होगी। मित्रों का सहयोग लेना हितकारी होगा। जो लोग आपके विरुद्ध थे, वे अचानक आपके पक्ष में आ सकते हैं।

मिथुन क, की, कु, क्य, ड, डक, के, के, ह

विदेश में कार्यरत लोगों को सम्मान मिल सकता है। व्यवसाय में रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। जाँब में बदलाव करने का विचार बनायेंगे। प्रेम सम्बन्धों में कुछ प्रतिकूलता रहेगी।

कर्क हि, ह, हे, हो, झ, झे, डे, डे, डे

कार्य क्षेत्र या घर में परिवर्तन अथवा साज सज्जा में बदलाव भी कर सकते हैं समाज के प्रतिष्ठित लोगों से सम्मान मिलेगा लेकिन आर्थिक लाभ थोड़ा विलम्ब से होगा। दाम्पत्य सुख उत्तम रहेगा।

सिंह मा, मी, यू, मे, मो, टा, टी, टू, टे

व्यवहार कुशलता व संतोष स्वभाव से सम्मानित होंगे। उधारी वसूलने में परेशानी आ सकती है। घर में मेहमानों के आने से वातावरण आनंदित होगा। पारिवारिक खर्च बढ़ने से परेशानी भी होगी।

कन्या टो, पा, पी, पू, ष, ष, ठ, थ, पो

मित्र परिजनों के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। फिजूल खर्चों से बचें। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहने से सप्ताह उत्साह पूर्ण रहेगा।

तुला रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते

संतान से पुराने मतभेद उभरने से पारिवारिक वातावरण अशान्त होगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ने से कर्ज लेना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र पर आर्थिक बिजली के बाद आज उदासीनता छापी रहेगी।

वृश्चिक तो, ना, नी, नू, या, यी, यू

नौकरी पेशाओं को आतिरिक्त कार्य मिलने से असुविधा होगी काम लापरवाही से करेंगे। मित्रों के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा। सरसाल से लाभ होगा। पारिवारिक दायित्व बढ़ने से व्यस्तता रहेगी।

धनु ये, यो, भा, भी, भू, धा, फ, द, धे

नौकरीपेशा जातकों को मेहनत का फल मिलेगा। विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। साहित्यकार, लेखक एवं पत्रकारों के लिए सप्ताह विशेष लाभदायक रहेगा।

कुंभ गू, गे, गो, सा, सी, सू, से, सो, दा

नए कार्यों का आरंभ आज ना करें ना ही किसी को उधार दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलने लगेगा लेकिन घरेलू आवश्यकताओं को नजरअंदाज करने से अपाति बढ़ेगी।

मीन दी, दे, धे, झ, ज, दे, दो, चा, वि

आर्थिक लाभ के लिए अधिक समय करना पड़ेगा मध्यम के प्रयत्न किसी मनोकामना को पूर्ति होने से प्रसन्न रहेंगे।

आचार्य राजेश शास्त्री, जयपुर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान शुरू



जागरूक जनता jagrukjanta.net

जयपुर। शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी राजन विशाल ने पंत कृषि भवन में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की पॉलिसियों का वितरण कर रबी 2024-25 की 'मेरी पॉलिसी मेरे हाथ' अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विशाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की कृषक हितेशी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए उनके निर्देश पर फसल बीमा योजना को और सरल बनाने व किसानों को ज्यादा लाभ प्रदान करने के लिए कृषि विभाग प्रयासरत है। कृषकों को समय पर बीमा पॉलिसी की हार्ड कॉपी नहीं मिलने से खराबा होने पर फसल की जानकारी एवं किसानों को बीमा के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिबिर लगाकर पॉलिसियों का वितरण 15 मार्च तक किया जायेगा। विशाल ने बताया कि मुख्यमंत्री की कृषक हितेशी नीतियों को मद्देनजर रखते हुए उनके निर्देश पर फसल बीमा योजना

जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज के दिव्य प्रवचन एवं मधुर संकीर्तन जिन्न TV चैनल पर अवश्य श्रवण करें

सुश्री श्रीधरी देवी

NEWS 18 इंडिया प्रसारित (घाट) EVERY DAY 5:30 AM

न्यूज 24 प्रसारित (घाट) EVERY DAY 6:00 AM

भारत समाचार प्रसारित (घाट) EVERY DAY 6:50 AM

साधुना प्रसारित (घाट) EVERY DAY 8:15 AM

संस्कार प्रसारित (घाट) MON - SAT 8:30 PM

You Tube JagadguruKripaluJIMaharaj

You Tube ShreedhariDidi

गौड़ ब्राह्मण महासभा का युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन 9 मार्च का, आवेदन 10 फरवरी तक



जागरूक जनता

जयपुर @ जागरूक जनता। गौड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा 9 मार्च रविवार को आयोजित होने वाले युवक युवती वैवाहिक परिचय सम्मेलन के लिए प्रथम पुज्य गणेश जी महाराज मोती डूंगरी को निमंत्रण प्रस्तुत किया गया और प्रार्थना की गई कि इस मंगल कार्य को सफल बनाने की कृपा करें। इस अवसर पर गौड़ ब्राह्मण महासभा के प्रदेश महामंत्री रामस्वरूप जोशी कल्याणदत्त शर्मा जोधराज शर्मा तनिक शर्मा और नीलेश शर्मा द्वारा उपस्थित होकर प्रथम पुज्य की सेवा में आयोजित की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। युवा जोधराज शर्मा ने बताया कि परिचय सम्मेलन में आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 फरवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी गई है। तनिक जोशी ने बताया कि इसमें डॉक्टर इंजीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट राजकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी व्यापारी निजी व्यवसाय आदि सभी प्रकार कि प्रविष्टि का समावेश समाज की युगल दर्पण स्मारिका में किया जाएगा।

बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि बदली

जयपुर/अजमेर @ जागरूक जनता। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा की एक अप्रैल एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा की 4 अप्रैल को होने वाली परीक्षा की तिथियों में संशोधन किया गया है। बोर्ड सचिव केलाश चन्द्र शर्मा ने बताया कि टाइम टेबल के अनुसार 1 अप्रैल मंगलवार को तृतीय भाषा-संस्कृत/उर्दू/गुजराती/सिन्धी/पंजाबी, संस्कृत (द्वितीय प्रश्न पत्र) की परीक्षा अब 4 अप्रैल को होगी। इसी तरह उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व्यावसायिक एवं वरिष्ठ उपध्याय परीक्षा के टाइम टेबल में 4 अप्रैल को होने वाली कम्प्यूटर विज्ञान/इन्फोरमेटिक्स प्रैक्टिस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को ली जाएगी। बोर्ड प्रशासन के अनुसार एक अप्रैल को दूसरी की संस्कृत व अन्य भाषाओं की परीक्षा तय थी। लेकिन 31 मार्च को ईद का अवकाश है। यदि चांद दिखाई नहीं दिया तो अगले दिन ईद एक अप्रैल को होगी। जबकि 12 वीं की 4 अप्रैल को कम्प्यूटर शिक्षा से जुड़ी परीक्षा के दिन नेशनल टैस्टिंग एजेंसी की भी परीक्षा है।

₹ FeesPe THE POWERFUL WAY TO FEE COLLECTION

+91 820-910-0012

India's 1st FREE Fees

Collection Portal

Best User for All type - School | College | Institute | University

Accepted All Mode - Cash | Cheque | UPI | Credit-Debit Card | Net Banking | Wallet

REGISTER NOW

www.feespe.com



जागरूक

Make India Great Again



बजट 2025	ग्रामीण विकास	शिक्षा	स्वास्थ्य	रक्षा
	2.66 लाख करोड़ 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों से गांवों को मिलेगा बूस्ट, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को बॉडबैंड से जोड़ा जाएगा	1.28 लाख करोड़ मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 सीटें जोड़ी जाएंगी, सभी सरकारी मिडिल स्कूलों में बॉडबैंड	98311 करोड़ 36 जीवन रक्षक दवाओं को बेसिक सीमा शुल्क से छूट। इसके अलावा 37 और दवाओं व 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों को भी बेसिक सीमा शुल्क से छूट	4.91 लाख करोड़ विमान और एयरो इंजन पर खर्च होगा बड़ी राशि। नौसेना बेड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में रक्षा निर्यात में 32.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई

12 लाख तक की इनकम पर अब टैक्स नहीं, किसानों की कर्ज लिमिट पांच लाख

सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे

आम आदमी को बड़ी राहत, अब 12 लाख तक कमाई पर टैक्स में छूट

बजट क्लास, मिली सांस

नौ करीपेशा मिडिल क्लास की आस आखिरकार पूरी हो गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री करने का बड़ा ऐलान किया है। अब इस सीमा तक की कमाई पर सरकार का हिस्सा नहीं होगा। शनिवार को संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने किसानों को भी राहत का ऐलान किया। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट में इजाफा कर इसे तीन से पांच लाख रुपए कर दिया है। इस बजट में सभी का ध्यान रखा गया है, पर मिडिल क्लास को खास तवज्जो दी गई है। टीडीएस के मोर्चे पर बुजुर्गों को भी बड़ी सुविधा का ऐलान किया गया है। बजट में कुछ ऐसे प्रावधानों का भी जिक्र किया गया है, जिससे 36 जीवन रक्षक दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, मोबाइल फोन समेत कुछ चीजें सस्ती भी होंगी।



जागरूक जनता jagrukjanta.net

बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए चार इंजन...कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को चिन्हित किया गया है। सीतारमण ने नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आकर से छूट देने की घोषणा की। साथ ही कर स्लेब में भी बदलाव किया है। आयकर छूट नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले आयकरदाताओं को मिलेगी। वेतनभोगी करदाताओं के लिए 75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ अब 12.75 लाख रुपये पर कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 12 लाख रुपए की आय पर कर छूट की घोषणा से करीब एक करोड़ और लोग कर के दायरे से बाहर हो जाएंगे। सीतारमण ने संसद में 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा, नई कर व्यवस्था में छूट के माध्यम से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके

हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत की दिशा में लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग हमारे प्रमुख समर्थक स्तंभ हैं। मध्यम वर्ग भारत की वृद्धि को ताकत प्रदान करता है, उनके योगदान को देखते हुए, हमने उनके कर के बोझ को समय-समय पर कम किया है। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर छूट सीमा को मौजूदा 50,000 रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है। सीतारमण ने लोकसभा में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका भी पेश किया। उन्होंने बीमा क्षेत्र में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेश निवेश) की सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने के साथ ही कर कानूनों को सरल बनाने का भी प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि सरकार कराधान, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र, बिजली और नियामकीय ढांचा जैसे छह क्षेत्रों में सुधारों की शुरुआत करेगी।

नया टैक्स स्लेब-2025

0 से 4 लाख रुपए तक-	कोई टैक्स नहीं
4-8 लाख रुपए तक-	5 फीसदी
8 से 10 लाख रुपए तक-	10 फीसदी
12 से 16 लाख रुपए तक-	15 फीसदी
16 से 20 लाख रुपए तक-	20 फीसदी
20 से 24 लाख रुपए तक-	25 फीसदी
24 लाख से अधिक कमाई पर-	30 फीसदी

नोट- 12 लाख पर इनकम में टैक्स फ्री, 12 लाख से अधिक होने पर यह टैक्स स्लेब लागू होगा।

अब कितना फायदा

कमाई	टैक्स बेनीफिट
12लाख	80 हजार रुपए
16 लाख	50 हजार रुपए
18 लाख	70 हजार रुपए
20 लाख	90 हजार रुपए
25 लाख	1.10 लाख रुपए

व्या सस्ता-व्या महंगा

सस्ता	36 जीवन रक्षक दवाएं, कैन्सर की दवाएं, इलेक्ट्रिक गाड़ी, मोबाइल फोन, मोबाइल बैटरी, फिश पेट, लैपटॉप गैजेट, एलईडी टीवी
महंगा	फ्लैट पेंशन डिस्पेंसे, टीवी डिस्पेंसे, फैब्रिक

किसानों की बल्ले-बल्ले

- किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई
- देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।
- डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन
- समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई
- अंडमान, निकोबार और गंडर समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा
- बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा
- मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा
- दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन
- पोस्ट एमेंट बैंक पोस्ट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी
- कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना।

- मध्यम वर्ग के लिए राहत का पिता
- अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं
 - बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई
 - टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई
 - 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे।
 - किराया आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपए की गई
 - मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
 - ईवी और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी
 - एलईडी-एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5%
 - देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा
 - 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा
 - शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी
 - एक लाख अक्षर घरे पुरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे
 - हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा
 - बिहार की बल्ले-बल्ले
 - आम बजट में बिहार को खास तवज्जो दी गई है। ऐसी चर्चा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सौगात दी गई है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण, एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान भी स्थापित किया जाएगा।
 - पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार किया जाना भी प्रमुख घोषणाओं में शामिल है। बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने और आईआईटी, पटना में छात्रावास और एक अन्य बुनियादी ढांचा क्षमता के विस्तार की भी घोषणा हुई है।

उड़ान योजना से जुड़ेगे 120 नए शहर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में उड़ान योजना के तहत 120 नए रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की घोषणा की। बजट के अनुसार, उड़ान योजना के लिए आवंटन हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा और पूर्वोत्तर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी के लिए एक नई योजना भी तैयार की गई है।

किराए पर टीडीएस की सीमा 6 लाख

बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराए पर लावू टीडीएस (टैक्स डिड्यूटेड ग्रेट सोर्स) की सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह सीमा 2.4 रुपये लाख थी, जिसके ऊपर किराए पर टीडीएस काटा जाता था। नई सीमा से अब 6 लाख रुपए तक के वार्षिक किराए पर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यह बदलाव छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फायदेमंद है क्योंकि इससे टीडीएस कटौती और फाइलिंग को प्रक्रिया आसान होगी।

बुजुर्गों को टीडीएस के मोर्चे पर राहत

आम बजट 2025-26 में इनकम के मोर्चे पर टैक्स डिड्यूशन की दरों में कटौती के लिए न्यूनतम आय की सीमा को बढ़ाया है। बुजुर्गों को ब्याज से मिलने वाले आय पर टीडीएस कटौती की सीमा 50 हजार रुपए सालाना से बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई।

मध्य वर्ग, कृषक और श्रमिक उत्थान का बजट : साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वह वचन फिर से पूरा हुआ है कि जिन्हें कोई नहीं पूछता, उन्हें मोदी जी पूछते हैं। समाज के मध्य वर्ग, कृषक और श्रमिक वर्गों के उत्थान के लिए यह बजट ऐतिहासिक और क्रांतिकारी होगा। यह भारत के सुनहरे भविष्य का दस्तावेज है। स्वतंत्र भारत के इतिहास के चंद्र ऐतिहासिक बजटों में से यह एक है। देश के टैक्स पेयर और मध्यम वर्ग का सम्मान करते हुए मोदी सरकार ने एक ऐसा निर्णय लिया है जिसकी कल्पना भी लोगों को नहीं थी, पूर्व की सरकार में जहां 2 लाख रुपए की आय पर टैक्स लगता था, मोदी सरकार में 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा।

- स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
- 500 करोड़ रुपए से 3 एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सप्लोरेशन सेंटर बनेंगे
- मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी
- देश में 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
- पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएंगी।
- देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मेसुरिफ्ट का डिजिटलाइजेशन होगा।
- पटना आईआईटी में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।

जुबानी तीर

आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बजट से आम आदमी को बहुत फायदा मिलेगा। इससे बड़ा परिवर्तन आएगा। इससे आत्मनिर्भर भारत को गति मिलेगी। देश में टूरिज्म बढ़ा है। टूरिज्म से रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। पार्लियुप संरक्षण की दिशा में कदम उठा रहे हैं।

गोली के घाव पर मरहम पट्टी वाला बजट

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, 'गोली लगेने के घाव के लिए एक मरहम पट्टी!' आरोप लगाया कि वैश्विक अनिश्चिता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बजट की आवश्यकता है, लेकिन यह सरकार विचारों को लेकर दिवालिया है।

घोर निराशाजनक बजट : बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, आम जनता के लिए घोर निराशाजनक बजट है। शेंयर बाजार बैट गया है, निवेशक बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। डॉलर 86 रुपए 70 पैसा से पार हो गया है। बाजार लगातार गिर रहा है, मोदी सरकार के आर्थिक नीतियों पर से जनता का भरोसा टूट चुका है। श्री बघेल ने कहा, मोदी सरकार के बजट से देश का हर वर्ग निराश है। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब, किसान, मजदूर और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। यह बजट पूरी तरह से और अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण और मिडिल क्लास विरोधी है।

उद्योग और व्यापार जगत

- एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी
- सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव
- 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे
- उत्तोल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे
- देश को खिलौना उत्पादन का क्लोनल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी
- नई लेबर स्कॉम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा

आमजन को बड़ी राहत पहुंचाने वाला जनहितैषी बजट
यह बजट आमजन के साथ साथ हर वर्ग को बड़ी राहत पहुंचाने वाला उत्कृष्ट बजट है। जिसमें कई बड़ी जनहितैषी घोषणाओं का ऐलान किया गया। जिसका फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। इस बजट में किसान और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने पर सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। जिससे मध्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है। महिलाओं के लिए बजट में दो बड़े ऐलान किये गये हैं, जिसके तहत SC-ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना और पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। बुजुर्गों के लिए भी बड़े ऐलान इस बजट में हुए हैं। सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी है।

अरविन्द अग्रवाल
एमडी, भगवती रिजॉर्ट, आबू रोड, सिराही

टैक्सपेयर को बड़ी राहत
यह बजट सामान्य नागरिक, विकसित भारत के मिशन को पूरा करने वाला है। ये बजट इन्वेस्टमेंट, कन्जमेशन को बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री और उनकी टीम को जनता का बजट बनाने के लिए बधाई देती हूँ। बजट 2025 नौकरीपेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लेब का टैक्स सरकार माफ करेगी। बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। साथ ही अब सभी टैक्सपेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। इससे पहले तक यह लिमिट 2 साल थी।

डॉ. रक्षाबंधन
जिलाध्यक्ष, भाजपा, सिराही

सभी के लिए अद्भुत बजट
यह बजट विकसित भारत और प्रधानमंत्री मोदी के नए और ऊर्जावान भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प के लिए है। यह एक क्रेडिट बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा और न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि इसे विश्वगुरु के रूप में स्थापित करेगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने गरीबों, मध्यम वर्ग और सभी के लिए एक अद्भुत बजट पेश किया गया है। प्रवक्ता खत्री ने बताया कि इस बजट में युवाओं पर विशेष फोकस करते हुए मोदी सरकार स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा, 500 करोड़ रुपए से 3 A1 (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) एक्सप्लोरेशन सेंटर बनेंगे।

रोहित खत्री
जिला प्रवक्ता, भाजपा, सिराही

बजट में खास



टीडीएस/टीसीएस की दरों में दी राहत

अब धनप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपए

उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर-पैन मामलों पर ही लागू होंगे।

लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन से अपनी आय संबंधी व्ययों को दिया

छोटे धर्मार्थ न्यासों/संस्थाओं की पंजीकरण अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष की

एनपीएस वात्सलय खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव

अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के मामलों में आर्म्स लेन्य मूल्य निर्धारण करने के लिए एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है।

आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की समय-सीमा 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई

ऐसे आयातकों को केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा

ओल्ड टैक्स रिजीम में बदलाव नहीं



बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स प्रती रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत करदाताओं को 5 लाख तक की इनकम पर 12,500 रुपए माफ करते हैं अर्थात् कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपको सालाना इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स लगेगा। यानी आपको 1,12,500 रुपए टैक्स चुकाना होगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में ऐसे कई प्रावधान यानी टैक्स छूट हैं, जिनसे आप 10 लाख तक की इनकम टैक्स प्रती कर सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपकी आय 5 लाख से 1 रुपए भी ज्यादा होती है तो आपको 87ए का फायदा नहीं मिलेगा। आपको 2.5 लाख से ज्यादा की इनकम पर टैक्स चुकाना होगा। हालांकि, वेतनभोगी लोगों को 5.50 लाख रुपए तक की रकम टैक्स प्रती होती है। उन्हें 50 हजार रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है।



साल 2019 साल 2020 साल 2021 साल 2022 साल 2023 2024 अंतरिम साल 2024 साल 2025

नई टैक्स रिजीम वाले फायदे में, पुरानी जस की तस तक 'कमाई' पर 80 हजार का फायदा



जागरूक जनता jagrukjanta.net

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी है। इस बार वित्त मंत्री सीतारमण ने 77 मिनट लंबा बजट भाषण दिया। इस बार न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए तक हो जाएगी। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई

पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न फाइल कर सकेने

सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस बढ़ाकर एक लाख रुपए

नई टैक्स रिजीम के दूसरे और तीसरे स्लैब में कर माफ

पहला लाभ। इस साल की नई टैक्स रिजीम के दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87ए के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 हजार का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को कुल 12.75 लाख की आय टैक्स प्रती हो जाएगी। ध्यान रहे कि यह राहत केवल नौकरीपेशा लोगों के लिए है। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही रहेगी। दूसरा लाभ, आयकरदाता पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेने। इससे पहले तक यह सीमा 2 साल की थी। तीसरा लाभ है कि सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी है।

नए टैक्स स्लैब से कितना फायदा

सालाना आय	टैक्स	सालाना आय	टैक्स
0-3 लाख	कुछ नहीं	0-4 लाख*	कुछ नहीं
3-7 लाख	05%	4-8 लाख*	05%
7-10 लाख	10%	8-12 लाख*	10%
10-12 लाख	15%	12-16 लाख	15%
12-15 लाख	20%	16-20 लाख	20%
15 लाख से ज्यादा	30%	20-24 लाख	25%
-	-	24 लाख से ज्यादा	30%

नोट: *न्यू टैक्स रिजीम में 4-8 लाख पर 5% टैक्स और 8-12 लाख पर लगने वाला 10% सरकार सीधे माफ कर देती है।

सरकार कर रही प्रोत्साहित

ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू टैक्स रिजीम के दायरे में आएँ

नौजुब समय में दो तरह के आयकर सिस्टम हैं। न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। वर्तमान में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में 65 फीसदी से ज्यादा करदाता न्यू टैक्स रिजीम को अपना चुके हैं, यानी हर 3 में से 2 लोग न्यू टैक्स रिजीम के तहत आयकर फाइल कर रहे हैं। इस डेटा में पिछले एक साल के दौरान ज्यादा बदलाव आया है, क्योंकि सरकार ने जब बजट 2020 में न्यू टैक्स रिजीम को लागू किया तो लोग इसे अपनाने से कतरा रहे थे। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार एक नए बिल को लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर सकती है।

टीडीएस के बोझ को कम किया

- 50 लाख से अधिक मूल्य की विशेष वस्तुओं की बिक्री के स्रोत पर कोई कर नहीं लिया जाएगा।
- आय की विवरणों दाखिल नहीं करने वाले लोगों के लिए उच्च टीडीएस/टीसीएस दर को हटा दिया है। इसके तहत अधिनियम की धारा 206कए और धारा 206कनक को विलोपित की जाएगी।
- अधिनियम की धारा 206ग(7) के तहत 'वन उत्पाद' के अर्थ को तर्कसंगत और स्पष्ट करने का प्रस्ताव है ताकि इसकी परिभाषा से संबंधित किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर किया जा सके। टीडीएस किसी अन्य वन उत्पाद जो वन पट्टे के तहत प्राप्त किया जाता है पर ही अर्जित किया जाएगा।

इनकम टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहन

- पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेने। इससे पहले सीमा 2 साल तक की थी।
- इनकम रिटर्न फाइल करते समय इनकम टैक्स प्रेयर्स को फिल्टर कर सी में किए गए निवेश की भी जानकारी देनी होगी।
- पर अथवा उसके माग से मिलकर बनी संपत्ति का वार्षिक मूल्य शुल्क माना जाएगा। बजट में दो संपत्तियों पर वार्षिक मूल्य शुल्क मान्य किया गया है।

व्यापार के सरलीकरण के लिए ये बिंदु

- स्टार्ट-अप हेतु पांच वर्षों के लिए आईएससी की धारा 80 के तहत लाभ दिए जाएंगे।
- धर्मार्थ न्यासों व संस्थाओं के लिए कर प्रावधानों का सरलीकरण किया।
- छोटे न्यासों अथवा संस्थान के पंजीकरण की वैधता अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष की गई।
- व्यावसायिक न्यासों के करस्थान को युक्तिसंगत बनाना
- संबन्धित किए गए कर (टीसीएस) पर देरी से भुगतान के लिए छूट

बजट में सरकार की करों की कटौती और राहत का साइड इफेक्ट प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रु. और अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ का होगा नुकसान

36 जीवन रक्षक दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में करों की कई राहत से सरकार को प्रत्यक्ष करों में लगभग एक लाख करोड़ रुपए का और अप्रत्यक्ष करों में 2600 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। सरकार ने 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

हस्तशिल्प वस्तुओं की निर्यात अवधि बढ़ाई

बजट में हस्तशिल्प की निर्यात अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई, आवश्यकता पड़ने पर आगे तीन महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है। शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची में नौ और वस्तुएं शामिल की गई हैं। चमड़े की वस्तुओं में वेट ब्लू लेडर पर बुनियादी सीमा शुल्क में पूर्ण छूट दी गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं में छूट बढ़ाकर 20%

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं में छूट बढ़ाकर 20%। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पुंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण हेतु 28 अतिरिक्त पुंजीगत वस्तुओं पर छूट है। पौत विनिर्माण में कच्चे माल, घटकों, पुर्जों पर अगले दस वर्षों तक बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी गई है।

समूदी उत्पाद को बढ़ावा

समूदी उत्पाद को बढ़ावा। फ्रीजिंग फिश पेट्ट (सुरमी) और ऐसे ही उत्पादों के निर्यात पर बुनियादी सीमा शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। मछली और झींगा के आहार बनाने के लिए फिश हड्डि/लीक्रेट पर बुनियादी सीमा शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है। रेल वस्तुओं के लिए घरेलू एमआरओ में वायुयानों और जलपोतों के मरम्मत के लिए आयोजित एमआरओ के समान ही छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसी वस्तुओं के निर्यात की समय-सीमा छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की गई।

कर सुधारों को लेकर नया कानून अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल, सरल भाषा में होगा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल को संसद में रखा जाएगा जिससे कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। संभवतः टैक्स रिजीम में फेरबदल होने वाला है। दरअसल, अब नया आयकर कानून को बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाएगा। यह एक नया कानून होगा, न कि मौजूदा अधिनियम में संशोधन। यह मसौदा विधि मंत्रालय के पास था। नया आयकर कानून लाने का मुख्य मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्स, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है।

आम बजट पर खास नजरिया

बजट में भारत के आर्थिक भविष्य की एक दूरदर्शी और व्यावहारिक योजना



डॉ. अरुण अग्रवाल मानद महासचिव एवं प्रवक्ता राज चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री

केंद्रीय बजट 2025-26 भारत के आर्थिक भविष्य की एक दूरदर्शी और व्यावहारिक योजना प्रस्तुत करता है। इस बजट में तीन प्रमुख बदलाव उभरकर सामने आते हैं- आर्थिक सशक्तिकरण, सतत विकास और सुशासन में क्रांति। आर्थिक सशक्तिकरण केवल कर राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि वित्तीय समावेशन पर केंद्रित है। एमएसएमई, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप को दो गंभीर वित्तीय सहयोगों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि समृद्धि केवल बड़े उद्योगों तक सीमित न रहे, बल्कि हर स्तर तक पहुंचे। सतत विकास का संकेत नए शहरीकरण मॉडल से मिलता है। 'अर्बन पैलेज फंड' और ग्रीन सिटी योजनाओं से अत्यवस्थित विस्तार के बजाय सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल शहरों की नींव रखी जा रही है, जिससे भारत का शहरी जीवन बेहतर और टिकाऊ बने। सुशासन में बदलाव तकनीक-संचालित नीतियों के रूप में स्पष्ट है। एआई-आधारित सरकारी सेवाओं और तेजी से स्वीकृत होने वाली योजनाओं से शासन अधिक कुशल बनेगा।

बाजार में केश फ्लो बढ़ेगा, उद्यमी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में बड़ी पहल



पुरुषोत्तम अग्रवाल अध्यक्ष, राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन, जयपुर

बजट 2025 में इनकम टैक्स से बहुरतीक्षित राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 5 लाख रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलने करदाताओं की ओर से यह पूंजी बाजार में आएगी। बाजार में पूंजी प्रवाह (केश फ्लो) बनेगा। उनके पास अधिक पैसा छोड़ने, घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने का मौका होगा। न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसका कारण है कि सरकार निरंतर अधिक से अधिक लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में तहत लाना चाहती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा 50 हजार रुपए से बढ़ाकर एक लाख रुपए करके उन्हें बड़ी राहत दी गई है। इनकम टैक्स भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अब एकसाथ 4 साल तक का अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे। किराया आमदनी पर टीडीएस छूट सालाना 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए की गई है। पहली बार व्यापार करने वाली महिलाओं को बिना गारंटी के 2 करोड़ रुपए का ऋण उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा, लोगों को रोजगार दिलाएगा।



20

करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर पांच लाख

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले 'कस्टमाइज्ड' क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। अस्की तरह से संचालित निर्यातोनमुख्य एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।

1.7 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने पीएम धन धान्य कृषि

'प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना' की घोषणा से कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण समृद्धि व लचीला कार्यक्रम शुरू करेगी। सरकार दालों में आत्मनिर्भरता के लिए छह साल का कार्यक्रम भी शुरू करेगी, जिसमें तृण, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सब्जियों और फलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा।

1.7

करोड़ किसानों को 'धन धान्य योजना' लाभ मिलेगा।



₹ बजट में खास



उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा

असम के नामरूप में 12.7 टन सालाना क्षमता का यूरिया संयंत्र लगाया जाएगा



सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी घटी



सरकार दालों पर छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तृण, उड़द और मसूर पर रहेगा विशेष ध्यान

भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ अगले चार वर्षों में दलहन की खरीद करेंगे



पश्चिमी कोसी नहर के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी, बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ होगा

अन्नदाता होगा खुशहाल

कृषि खाद, कैमिकल, उपकरण कम्पनियों में बढ़ेगी ग्रोथ

किसानों के लिए इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने काफी उदारता दिखाई है। कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए छह नई योजनाओं की घोषणा की गई जिसमें सब्सिडी वाले किसान कार्ड से लेकर फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर चीज को बढ़ावा देना शामिल है। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से ऋण प्राप्त करने की सीमा को पांच लाख रुपये से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि उनका लक्ष्य देश भर में बेरोजगारी से लेकर फसल उत्पादकता बढ़ाने तक हर चीज को बढ़ावा देना है।

बजट में कृषि क्षेत्र के लिए छह नई योजनाएं

पलायन रोकने ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा होंगे अवसर

सीतारमण ने कहा, "इनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा करना है ताकि पलायन एक विकल्प रहे, लेकिन अनिवार्यता न होने पाये। युवाओं का यह कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और मूहिन परिचरों पर केंद्रित होगा।

दालहन को बढ़ाने छह साल का मिशन

दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक बड़े कदम के रूप में छह साल का मिशन अरहर, उड़द और मसूर उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा। इस पहल के तहत, सहकारी संस्थाएं नेफेड और एनसीसीएफ इन एजेंसियों के साथ समझौते करने वाले पंजीकृत किसानों से चार साल तक दालों की खरीद करेंगी।

बेरोजगारी से लेकर फसल उत्पादकता बढ़ाने पर जोर

सीतारमण ने कृषि को 'विकास का पहला इंजन' बताया



ये हैं छह योजना

- 1 किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी
- 2 पीएम धन-धान्य योजना
- 3 डेयरी व मछली पालन के लिए लोन
- 4 दालों का उत्पादन बढ़ाने मिशन
- 5 कपास उत्पादन के लिए कार्य योजना
- 6 मखाना बोर्ड का गठन होगा

ग्रामीण समृद्धि व मजबूत कार्यक्रम होगा लागू

राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में लागू की जाने वाली इस योजना से कृषि उत्पादकता बढ़ने, फसल विविधीकरण और कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे में सुधार के जरिये 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक व्यापक 'ग्रामीण समृद्धि और मजबूती' कार्यक्रम लागू करेगी।

मछली और जलीय कृषि को बढ़ावा

मछली और जलीय कृषि में दूसरे सबसे बड़े वैश्विक उत्पादक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए 60,000 करोड़ रुपये के समुद्री खाद्य निर्यात के साथ सरकार भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और दूर समुद्र में स्थायी मछली पकड़ने के लिए एक स्पेसिफिकेशन पेश करेगी और इसके लिए विशेष रूप से अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह पर ध्यान केंद्रित करेगी।

मनरेगा...जैसे था पहले, अब भी वैसा ही

ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2025-26 के केंद्रीय बजट में 1.88 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले बजट में आवंटन से लगभग 5.75 प्रतिशत अधिक है। बजट प्रस्तावों के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को 2024-25 के बजट में 1,77,566.19 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। हालांकि, 2024-25 का संशोधित अनुमान, जो मंत्रालय द्वारा किए गए व्यय की मध्यावधि समीक्षा है, 1,73,912.11 करोड़ रुपये रहा। यह शुरूआती आवंटन से 3,654.08 करोड़ रुपये कम है। प्रमुख ग्रामीण योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये रखा गया है जो पिछले वर्ष के समान है।



कपास की किस्मों को मिलेगा बढ़ावा

इसके अतिरिक्त, एक पांच वर्षीय कपास मिशन उत्पादकता में सुधार और 'एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टैपल' कपास किस्मों को बढ़ावा देने पर काम करेगा, जो कपास क्षेत्र के लिए भारत के एकीकृत 5-एफ दृष्टिकोण का समर्थन करेगा।



बजट के बाद कृषि शेयरों में उछाल



टाटा केमिकल्स में रही गिरावट

दूसरी ओर, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स 2.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ 490.05 रुपये पर, धानुका एग्रीटेक 2.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,403.45 रुपये पर, टाटा केमिकल्स 2.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 964.45 रुपये पर और कोरोमंडल इंटरनेशनल 1.46 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,783.50 रुपये पर बंद हुआ। बीएसई पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का शेयर 1.32 प्रतिशत की गिरावट के साथ 161.05 रुपये पर और मेगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का शेयर 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 167.10 रुपये पर बंद हुआ।

नमो ड्रोन दीदी का बजट हुआ दोगुना

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए आवंटन (41.66 प्रतिशत बढ़कर 8,500 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (छह गुना बढ़कर 616.01 करोड़ रुपये), कृषि उन्नति योजना (12.58 प्रतिशत बढ़कर 8,000 करोड़ रुपये) और नमो ड्रोन दीदी (दो गुना बढ़कर 676.85 करोड़ रुपये) बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का आवंटन 64.33 प्रतिशत बढ़कर 2,465 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पशुपालन और डेयरी कार्यक्रमों में यह दोगुना होकर 1,050 करोड़ रुपये हो गया है। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए पीएम-एफएमई योजना को 67 प्रतिशत अधिक आवंटन यानी 2,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है।



कृषि बजट आवंटन 2.75 फीसदी घटकर 1.37 लाख करोड़

सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि मंत्रालय का बजट आवंटन 2.75 प्रतिशत घटाकर 1.37 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि, इस कमी को भरपाई संबद्ध क्षेत्रों के लिए बड़े हुए आवंटन से हुई है, जिसमें मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए आवंटन को 37 प्रतिशत बढ़ाकर 7,544 करोड़ रुपये और खाद्य प्रसंस्करण के लिए आवंटन को 56 प्रतिशत बढ़ाकर 4,364 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है।

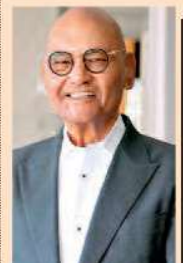
संकल्प की दिशा में स्वागत योग्य बजट



राजकुमार मिश्रल
अन्तरराष्ट्रीय अध्यक्ष
अन्तरराष्ट्रीय अग्रवाल
सम्मेलन

विकसित भारत के संकल्प की दिशा में 8वां ऐतिहासिक बजट है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए बजट में लोन गारंटी कवर 5 से बढ़ाकर 10 करोड़, स्टार्टअप के लिए ऋण राशि 10 से बढ़ाकर 20 करोड़ (सह ऋण कम गारंटी फंड के प्रावधान के साथ), होम स्टे योजना को बढ़ावा देने के लिए मृदा योजना के अंतर्गत ऋण देने एवं किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के सुझावों को बजट के प्रावधानों में शामिल करने से लघु मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिलेगा एवं नए रोजगार सृजन होने में सहायक सिद्ध होगा। बजट में महिलाओं के लिए पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा का प्रावधान महिलाओं में नई ऊर्जा, जाश का संचार होगा। प्रत्यक्ष कर में 12 लाख वार्षिक आय वर्ग को आयकर से मुक्त तथा टीडीएस की सीमा 10 लाख तक किए जाने से मध्यम वर्गीय व्यापारी एवं आमजन को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा 12 लाख आय वर्ग को आयकर मुक्त करके अधिक राहत दी है। कपास, दाल एवं मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाबद्ध तरीके से बजट में विशेष प्रावधान करने, देश में 23 आई आई टी में 6500 सीट, मेडिकल कॉलेज में 10000 सीट, मेडिकल एजुकेशन में 5 वर्षों में 75000 सीट बढ़ाने की घोषणा, उड़ान योजना के अंतर्गत 100 नए शहर को जोड़ने, 50 नए पर्यटन स्थलों के विकास की योजना, पहाड़ी क्षेत्रों में नए छोटे एयरपोर्ट, रिट्रिकल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर की घोषणा देश को विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अग्रवाल सम्मेलन परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व धन्यवाद करता है।

मैन्यूफैक्चरिंग-माइनिंग को बढ़ावा



अनिल अग्रवाल
चेयरमैन, वेदांता
लिमिटेड

बजट ने एकदम सही कदम उठाया है। 12 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की आय को पूरी तरह से इनकम टैक्स फ्री करके मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत दी है। यह मिडिल क्लास का सबसे बड़ा हिस्सा है। इससे 24 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स का बोझ भी काफी कम हो गया है। हमने एक वर्ल्ड-क्लास टैक्स सिस्टम की ओर निर्णायक कदम उठाया है जो सरल, पारदर्शी और टैक्सपेयर फ्रेंडली होगा। ये टैक्स परिवर्तन की भावना अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों में भी दिखाई देने वाली है, जिसके नीचे 'ट्रस्ट और सेल्फ-सर्टिफिकेशन' है। इससे मैन्यूफैक्चरिंग और माइनिंग को बहुत बढ़ावा मिलेगा। खुशी है कि माइनिंग अगले 5 वर्षों में परिवर्तनकारी सुधारों के लिए पहचाने गए 6 डोमेन में से एक है। माइनिंग के साथ-साथ कृषि भी एक प्राथमिकता, खासकर खाद्य तेल जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है। माइनिंग, कृषि, मैन्यूफैक्चरिंग (इलेक्ट्रॉनिक्स सहित), जो सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने, इम्पोर्ट कम करने और भारत में लाखों अच्छी नौकरियां पैदा करने में मदद कर सकते हैं।

बजट में खास

BUDGET 2025 बजट

क्षेत्रवार बजट आवंटन

विभाग	आवंटित राशि
सिग्नलिंग और टेलीकॉम	6,800 करोड़
विद्युत लाइनों का विस्तार	6,150 करोड़
स्टाफ कल्याण	833 करोड़
रेलवे स्टाफ ट्रेनिंग	301 करोड़
रेलवे जेफटी फंड	45,000 करोड़

बजट में रेलवे को भी कई सुगाते मिली हैं। बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि अगले वित्त वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 17,500 साधारण डिब्बे, 200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनें बनाने जैसी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने के बाद यहां रेल भवन में संवाददाताओं से बातचीत में रेलवे के लिए आवंटित परियोजनाओं एवं भावी परियंत्रय की जानकारी दी। उन्होंने कहा, बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जो चार से पांच साल में पूरी हो जाएंगी। ये नई रेल लाइन बिछाने, मौजूदा रेल लाइन का दोहराकरण करने, नए निर्माण, स्टेशनों के पुनर्विकास और फ्लाईओवर एवं अंडरपास जैसे कार्यों से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले दो-तीन वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें बनाई जाएंगी।

कुल बजट	राजस्व खर्च	पूंजीगत व्यय	नई रेलवे लाइनें	लाइन दोहराकरण
2,55,445 करोड़	3,445 करोड़	2,52,000 करोड़	32,235 करोड़	32,000 करोड़

रेल बजट 2025

बजट में 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल

200 वंदे भारत और 100 अमृत भारत ट्रेनों का तोहफा



सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी दी है। यह 2024-25 में आवंटित की गई राशि के लगभग बराबर है। रेलवे ने यात्रियों, माल और अन्य मर्दों से अधिक राजस्व का लक्ष्य रखा है। बजट 2025-26 में पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए कुल परियंत्रय 2,65,200 करोड़ रुपए में सामान्य राजस्व से 2,52,000 करोड़ रुपए, निर्भया फंड से 200 करोड़ रुपए, आंतरिक संसाधन से 3,000 करोड़ रुपए और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से 10,000 करोड़ रुपए शामिल हैं।

आय को लेखा जोखा

वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में माल दुलाई से आय 1,80,000 करोड़ रुपए रही, जबकि 2023-24 में वास्तविक राजस्व 1,68,199 करोड़ रुपए था। रेलवे ने एक बयान में कहा कि यात्री राजस्व लक्ष्य 13.2 प्रतिशत वृद्धि के साथ 80,000 करोड़ रुपए रखा गया है। माल राजस्व लक्ष्य 1,80,000 करोड़ रुपए पर बनाए रखा गया है, जो 2023-24 की तुलना में सात प्रतिशत अधिक है।



क्या कहते हैं एक्सपर्ट

हालांकि, विशेषज्ञों का एक वर्ग मानता है कि माल राजस्व में वृद्धि अपेक्षित अनुमानों के अनुसार नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक पूंजीगत व्यय किया गया है। सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर कुल व्यय 2024-25 के संशोधित अनुमान में 1,14,062 करोड़ रुपए और 2025-26 के बजट अनुमान में 1,16,514 करोड़ रुपए है। भारतीय रेलवे सालाना लगभग 4,000 किलोमीटर जोड़कर नेटवर्क विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। रेलवे ने पिछले 10 वर्षों के दौरान 31,180 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई हैं। भारतीय रेलवे सिमल इंजीनियरिंग एवं दूरसंचार संस्थान के पूर्व महानिदेशक शैलेंद्र कुमार गोयल ने कहा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सिमलिंग और दूरसंचार कार्यों के लिए सकल बजट परिवंत्रय 6,800 करोड़ रुपए है। अगले पांच वर्षों में 44,000 आरकेएम पर 'कवच' सुविधा देने की भारतीय रेलवे की योजना को देखते हुए, यह राशि अर्थात् है। हाल ही में हुई रेल दुर्घटनाओं के बाद भरोसा बहाल करने के लिए महत्वपूर्ण यात्री सुरक्षा कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

स्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

सरकार ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए भी बड़ा बजट दिया है। देशभर में ट्रेक विस्तार, नए पुलों, प्लेटफार्मों के विकास और नई तकनीकों के इस्तेमाल पर खास फोकस किया गया है। जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बने रेलवे लिंक का भी इस बजट में जिक्र किया गया है, जिससे उत्तर भारत के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

बुलेट ट्रेन व हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स

मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर (MAHSR), जिसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, के लिए इस बार अतिरिक्त फंड दिया गया है। सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि भारत में तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना हकीकत बन सके।

कमाई और भविष्य की योजनाएं

इसके साथ ही सरकार को उम्मीद है कि रेलवे 2025-26 में 3.02 लाख करोड़ रुपये कमाएगा। इसमें माल दुलाई से 1.88 लाख करोड़ रुपये और यात्री किराए से 92,800 करोड़ रुपये की आय होगी। खासकर, वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ने से यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना है।



पूंजीगत व्यय में मामूली कमी की

बजट 2025 में भारतीय रेलवे को तकनीकी सुधार, नई ट्रेनों और बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए बड़ा फंड मिला है। हालांकि, इस बार रेलवे के पूंजीगत व्यय में मामूली कमी की गई है, जिससे रेल कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई लेकिन सरकार का फोकस रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर बना हुआ है, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

विद्युतीकरण और माल दुलाई

सरकार के अनुसार पिछले 10 सालों में भारतीय रेलवे ने 41,655 किलोमीटर ट्रेक का विद्युतीकरण किया है। इससे ट्रेनों की स्पीड और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। इसके अलावा, भारतीय रेलवे ने इस साल 1,588 मिलियन टन माल की दुलाई की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।

3 रेलवे आर्थिक गलियारे बनेंगे

बजट में कहा गया है कि भारत में तीन प्रमुख रेलवे आर्थिक गलियारे बनेंगे। इनमें ऊर्जा, खनिज और सोमेट गलियारा, पोर्ट कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व वाला गलियारा शामिल होगा। बजट में पेंशन फंड में 66 हजार करोड़ रुपए रखे गए हैं। जबकि नई लाइनें बिछाने के लिए 32,235 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लाइनों के दोहराकरण में 32,000 करोड़ और गॉज लाइन में बदलने में 4,550 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है।

एक दशक से पकड़ी रफ्तार

देखा जाए तो पिछले दशक में रेलवे में सुधार की गति तेज रही है। 2014-15 में जहां प्रति दिन 4 किलोमीटर नए ट्रेक बिछाए जा रहे थे, वहीं 2023-24 में यह बढ़कर 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गया। पिछले दस वर्षों में 31,180 ट्रेक किलोमीटर का विस्तार किया गया है। इसी तरह 2014 से 2024 के बीच 41,655 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो 2014 से पहले के 21,413 रूट किलोमीटर के मुकाबले लगभग दोगुना है।

रेल मंत्री ने कहा, "नई अमृत भारत ट्रेनों के साथ हम कम दूरी वाले कई अन्य शहरों को भी जोड़ने का काम करेंगे।" ट्रेनों के भीतर सामान्य श्रेणी वाले डिब्बों की किल्लत के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस तरह के 17,500 डिब्बों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। वैष्णव ने कहा, "साधारण डिब्बों का निर्माण पहले से ही चल रहा है और 31 मार्च के अंत तक 1,400 ऐसे डिब्बे बनकर तैयार हो जाएंगे। अगले वित्त वर्ष में हमारा लक्ष्य 2,000 साधारण डिब्बे बनाना है। इसके साथ 1,000 नए फ्लाईओवर के निर्माण को भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि रेलवे 31 मार्च, 2025 तक माल दुलाई क्षमता से संबंधित एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा, हम 31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने का लक्ष्य हासिल कर लेंगे और भारतीय रेल दुनिया में माल दुलाई के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल चालू वित्त वर्ष के अंत तक 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल करने जा रही है। वैष्णव ने रेल संचालन की सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि सरकार ने इसके लिए आवंटन 1.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपये कर दिया है और अगले वित्त वर्ष में इसे 1.16 लाख करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।



आय में वृद्धि

बजट दस्तावेज में 2024-25 में यात्री और माल दुलाई सेवाओं, दोनों से आय में वृद्धि दिखाई गई है। उदाहरण के लिए, यात्री सेवाओं से प्राप्तियों के लिए 2024-25 के संशोधित अनुमान में 80,000 करोड़ रुपए दिखाए गए हैं, जबकि 2023-24 में इस मद के लिए वास्तविक राजस्व 70,693 करोड़ रुपए था।

रक्षा क्षेत्र : 6.81 लाख करोड़ से देश होगा सुरक्षित

- 9.53 प्रतिशत की बढ़ोतरी
- 1.9 प्रतिशत : जीडीपी का
- 1,80,000 करोड़ : सशस्त्र बल
- 1,48,722.80 करोड़ : उपकरण
- 4,88,822 करोड़ : वेतन
- 1,60,795 करोड़ : पेंशन
- 48,614 करोड़ : वैमानिकी इंजन

भारत ने चीन और पाकिस्तान से सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना के आधुनिकीकरण पर जोर देने के बीच, शनिवार को 2025-26 के लिए रक्षा परिवंत्रय के रूप में 6,81,210 करोड़ रुपए निर्धारित किए। यह चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित राशि 6.22 लाख करोड़ रुपए से 9.53 प्रतिशत अधिक है। कुल आवंटन में से 1,80,000 करोड़ रुपए सशस्त्र बलों के पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरणों की खरीद शामिल है। रक्षा के लिए बजट अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 1.9 प्रतिशत है और चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित आवंटन 6.41 लाख करोड़ रुपए से लगभग 6.2 प्रतिशत अधिक है।



इंजनों के लिए राशि

पूंजीगत व्यय के तहत विमान और वैमानिकी इंजनों के लिए 48,614 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं जबकि नौसेना बड़े के लिए 24,390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अन्य उपकरणों के लिए 63,099 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। नौसेना गोली परियोजनाओं के लिए 4,500 करोड़ रुपये का अलग से आवंटन किया गया है।

वेतन और पेंशन

अगले वित्त वर्ष के लिए दैनिक कामकाज और वेतन संबंधी राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपये आंका गया है, जिसमें पेंशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए शामिल हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 1.91 प्रतिशत होने का अनुमान है।

आत्मनिर्भर बनेगा भारत : राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बजट के लिए समग्र आवंटन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण को बड़ा बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा, रक्षा बलों के लिए 1,80,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत परिवंत्रय हमारे रक्षा बलों के आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं क्षमताओं में और मदद करेगा। यह उजट सुरक्षा को और मजबूत करेगा तथा देश को समृद्धि सुनिश्चित करेगा एवं विकसित भारत के सपने को साकार करने में एक बड़ी छलांग लगाएगा।

सैन्य उपकरणों की खरीदी

रक्षा मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय के बारे में कहा कि 1,48,722.80 करोड़ रुपए नए सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए 'आधुनिकीकरण बजट' पर खर्च करने की योजना है और शेष 31,277 करोड़ रुपए अनुसंधान एवं विकास तथा दायित्व परिपूरणियों के निर्माण पर खर्च की जाएंगे। आधुनिकीकरण बजट का 75 प्रतिशत राशि 1,11,544 करोड़ रुपए घरेलू उद्योगों से खरीद के लिए निर्धारित किए गए हैं। घरेलू हिस्से का 25 प्रतिशत राशि 27,886 करोड़ रुपए घरेलू क्लिनी उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए प्रावधान किया गया है।

13,500 करोड़ नहीं हुए खर्च

2024-25 के लिए 6.22 लाख करोड़ रुपए के बजटीय अनुमान के मुकाबले आवंटन में वृद्धि 9.53 प्रतिशत है। वर्ष 2024-25 में पूंजी परिवंत्रय 1.72 लाख करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान के अनुसार यह राशि 1,59,500 करोड़ रुपए है, जो बताता है कि लगभग 13,500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक खर्च नहीं की गई है।

आम बजट पर खास नजरिया



अब नौकरी लेना नहीं, नौकरी देना है। क्योंकि बजट में इस बात को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री ने उद्यमियों के लिए 10 लाख क्रेडिट कार्ड प्रथम वर्ष में जारी करने का संकल्प लिया है। जिसमें हर कार्ड में जो नए उद्यमी हैं वो 5 लाख की लिमिट उपयोग कर सकेंगे। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। इससे कॉलेज से जो बच्चे पासआउट हुए हैं, उन्हें अपना छोटा स्टार्टअप करने में प्रेरणा मिलेगी। - संजय बियानी, डायरेक्टर, बियानी ग्रुप कॉलेज



केन्द्र द्वारा इस बजट के माध्यम से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रणनीति प्रस्तुत की गई है। जहां तक वर्ष 2025-26 का प्रश्न है, इसमें पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया है। जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के स्वयं औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, रोजगार में वृद्धि, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, शहरी एवं ग्रामीण विकास, रक्षा और रेलवे क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में किये गये प्रावधानों को बढ़ाया गया है। - नगेन्द्र वशिष्ठ, समाजसेवी



बजट में 12 लाख तक आयकर नहीं देना होगा, की घोषणा कर प्रशासनीय कार्य किया है। कहीं हद तक आम नागरिक के कोचन की व्यवस्था टिके होगी। ऐसी कल्पना है। यह बजट डबल इंजन वाला कहलायेगा, जिसका पहला इंजन कृषि है और दूसरा इंजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग होंगे। दोनों का विकास कर विकसित भारत तथा मेक-इन-इंडिया की कल्पना को साकार करने की बात कही गयी है। हमारी मांग थी कि आयातित तेल एवं दालों पर निर्भरता कम हो, इसके लिये सरकारी बजट में प्रावधान करें। खाद्य तेलों के लिये नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयलसीड का गठन कर किसान की तिलहन की पैदावार बढ़ाने की क्षमता को अधिक मजबूत करना चाहती है, ताकि तिलहन की अधिक पैदावार ली जा सके। दालों के लिये आत्मनिर्भर दाल मिलनर को छह वर्ष के लिये लॉन्च करने की बात कही है जिसमें तुअर, उडद व मसूर की पैदावार पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा, जिससे दालों के निर्यात पर निर्भरता कम होगी। एक राष्ट्रीय मिशन उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के लिये केन्द्र सरकार बनायेगी। रिसर्च कार्य तीव्र गति से चलेंगे। बीजों का निर्यातित विकास सुनिश्चित किया जायेगा। बाबूलाल गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, नई दिल्ली

सभी वर्ग को राहत देने वाला बजट राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत ने केंद्रीय बजट पर प्रतिनिधि या देते हुए बताया कि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में आज पेश किए गये बजट में सभी वर्गों के लिए घोषणा कर राहत प्रदान की गई है। सांसद गहलोत ने बताया कि बजट में किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई प्रावधान किए हैं किसानों के डििट कार्ड की लिमिट पांच लाख तक बढ़ाकर राहत प्रदान की है, वहीं जीवन रक्षक दवाए टीवी मोबाइल सस्ती करने की घोषणा से हर वर्ग को राहत मिलेगी। वित्त मंत्री ने नीट में दस हजार नई सीटों की घोषणा कर विद्यार्थी व युवा वर्ग को राहत प्रदान की है। मध्यम व नौकरी पेशा के लिए 12.00 लाख तक की कर्माई को टेक्स मुक्त करते हुए बड़ी राहत प्रदान की गई है। जिससे बाजार में रुपयों की आवक व आमजन की खर्च सीमा बढ़ेगी राज्यसभा सांसद गहलोत ने बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश चहुँमुखी विकास के साथ विश्व की चौथी अर्थ व्यवस्था बनने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने ऐतिहासिक समावेशी विकासोन्मुखी बजट पेश कर देश की जनता को राहत प्रदान की है।

स्विस राजदूत ने की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी से मुलाकात

पर्यटन को बढ़ावा, तकनीकी सहयोग सहित विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा



जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी से सोमवार को उप मुख्यमंत्री कार्यालय में स्विस राजदूत माया तिस्साफ्री ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राज्य सरकार एवं स्विस सरकार के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शॉर्ट टर्म स्किल डवलपमेंट कोर्स संचालित करने, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने में सहयोग करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही ट्रेफिक मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन आदि क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग पर भी दोनों के बीच में सकारात्मक चर्चा हुई। इस दौरान स्विस राजदूत ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर के स्थापत्य, कला एवं आतिथ्य की जमकर सराहना की।

घर-घर रूफ टॉप लगाने की दिशा में जयपुर डिस्कॉम की नई पहल

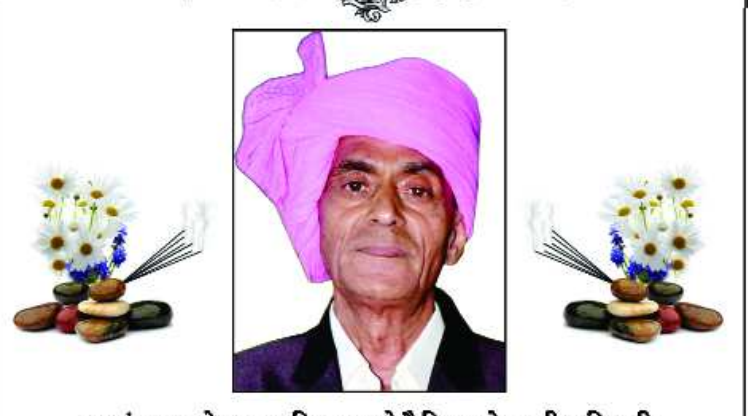
पीएम सूर्य घर योजना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 12 तकनीकी कार्मिकों को प्रोत्साहन चेक, प्रतिमाह सम्मानित होंगे तकनीकी कार्मिक



जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। जयपुर विद्युत वितरण निगम ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले तकनीकी कार्मिकों को प्रोत्साहित करने की अगुआई पहल की है। इसके अन्तर्गत रूफ टॉप सोलर लगाने का लक्ष्य अर्जित करने वाले जयपुर शहर के दोनों सर्किल तथा जयपुर जिला सर्किल (उत्तर) के 12 तकनीकी कार्मिकों को संबन्धित अधीक्षण अभियंताओं के स्तर पर सम्मानित किया गया है। इन तकनीकी कार्मिकों को एक-एक हजार रूपए के चेक प्रदान किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि डिस्कॉमस चेरमैन सुश्री आरती डोगरा ने इस संबंध में नवाचार करते हुए योजना में रूफ टॉप सोलर इंस्टालेशन का लक्ष्य प्राप्त करने वाले तकनीकी कार्मिकों के लिए मासिक प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसी की अनुपालना में प्रतिमाह 10 अथवा उससे अधिक रूफ टॉप सोलर स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कार्मिकों के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। डिस्कॉम के अन्य सर्किलों में भी इसी आधार पर तकनीकी कार्मिक सम्मानित किए जाएंगे। डिस्कॉमस चेरमैन को इसके पीछे मंशा यह है कि इससे कार्मिकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, वे अधिक मनोयोग से इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि इससे मुख्यमंत्री भजनलाल की राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की मंशा को और गति मिलेगी।

शोक संदेश



अत्यंत दुःख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पूजनीय पिताजी
श्री रमेश चन्द्र शर्मा

का देवलोकागमन दिनांक 01/02/2025 शनिवार को हो गया है। जिनका एकादशी व जागरणदिनांक 12.01.2025 बुधवार का एवं द्वादशी एवं शीशी पूजन 13.01.2025 को है।

प्रेषक
रोहित पाराशर
मो. 7790812485

सौकायिक
गंगादेवी (धर्मपत्नी), ओमप्रकाश शर्मा (प्राता), पवन, सुरेश, विष्णु (पतीते), अनुराग, मोहित, यश (पौत्र) एवं समस्त पाराशर परिवार।

निवास : 20, मारुति कॉलोनी, श्योपुर रोड, सांगानेर, जयपुर (राज.)



पंचायतीराज सशक्तिकरण एवं अभिनन्दन समारोह
द्वारा पंचायतीराज सशक्तिकरण एवं अभिनन्दन समारोह
मंगलवार, दिनांक : 04 फरवरी, 2025, मानसरोवर, जयपुर
हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन

किसानों-पशुपालकों की उन्नति से ग्रामोदय का सपना होगा साकार- मुख्यमंत्री शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गरीब, किसान और पशुपालकों को मजबूती देकर ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर और चौधरी चरण सिंह के ग्रामोदय के स्वप्न को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का फोकस गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने पर है।

शर्मा मंगलवार को सरपंच संघ राजस्थान द्वारा आयोजित पंचायतीराज सशक्तिकरण एवं अभिनन्दन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरपंचों के हाथों में गांवों के विकास की बागडोर होती है और समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उद्धार में सरपंच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होता है। श्री शर्मा ने कहा कि यदि उनकी इच्छाशक्ति मजबूत हो, दूरदृष्टि हो और लोगों का साथ हो तो गांवों का कायाकल्प किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि के रूप में सरपंचों के पास लोगों की सेवा का अवसर होता है और इसी सेवाभाव के साथ राजस्थान के प्रतिभाशाली और समर्पित सरपंच अपने गांवों को विकास की राह पर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सरपंच के रूप में अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि आप लोगों को देखकर मेरा हृदय आज उसी भाव से भर उठा है, जब मैं सरपंच था। उन्होंने कहा कि मैं गांव की मिट्टी में ही पला-बढ़ा हूँ और उसी मिट्टी की सौंधी खुशबू और चुनौतियों के बीच जिया हूँ।

राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध-शर्मा



भगवान देवनारायण जी की 1113वीं जयंती गुर्जर समाज का देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। गुर्जर समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं कौशल के उचित अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही, समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। शर्मा बिड़ला सभागार में देवनारायण जी की 1113वीं जयंती (4 फरवरी) के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज समर्पण से कार्य कर देश की अर्थव्यवस्था और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है। समाज ने न

किसानों को मिलेगी डिजिटल पहचान, ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त करने के लिए डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टैक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट को आज से सम्पूर्ण राजस्थान में लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 5 फरवरी से 31 मार्च तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। जहाँ किसानों की फार्मर आई.डी. बनाई जाएगी। सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक चलेंगे शिविर। इन शिविरों में किसान जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगला पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण, पशु चिकित्सा एवं उपचार सहित पशु पालन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभांशित किया जाएगा।

बेहद सरल है किसान आईडी बनवाने की प्रक्रिया

सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविरों का कार्यक्रम जिला कलक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है जिसकी जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए पोर्टल भी बनाया गया है। पोर्टल WWW.Rjfr.Rajasthan.gov.in से आप अपने शिविर की तिथियों व स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शिविरों में किसान को रजिस्ट्रेशन होने पर एक एनरोलमेंट स्लैप दी जाएगी। जिसके 24 घंटे के अंदर किसान के मोबाइल नंबर पर फार्मर रजिस्ट्री मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।

किसान को मिलेगी 11 अंकों की एक विशिष्ट पहचान

किसान रजिस्ट्री, एग्रीस्टैक परियोजना के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को एक पहल है। कृषक विवरण, उसके द्वारा धारित कृषि भूमि का विवरण, प्रत्येक कृषि भूखण्ड के जीपीएस निर्देशांक, उस पर बोई गई फसलों का विवरण आदि को डिजिटल रूप में संकलित किया जाकर, प्रदेश के प्रत्येक किसान को 'आधार' आधारित एक 11 अंकों की एक यूनिक आईडी (विशिष्ट किसान आईडी) आवंटित की जाएगी, जिससे किसान डिजिटल रूप से अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे। किसान आईडी डिजिटली सत्यापन योग्य पहचान है, जिसे www.rjfr.agristack.gov.in पोर्टल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। फार्मर आईडी जनरेट होने के बाद भूमि संशोधन (खसरा जोड़ने या हटाने) के लिए पटवारी, भू-अभि. निरीक्षक या तहसीलदार से सम्पर्क किया जा सकता है। इस हेतु मोबाइल एप/वेबसाइट द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों के स्वामित्व वाले सभी खसरा को सन्मिलित करते हुए कृषक के 'आधार' से लिंक कराया जायेगा, तत्पश्चात कृषक से ऑनलाइन सहमति प्राप्त करते हुए ई-हस्ताक्षर की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

Best Deal

New & Used Car

Minimum Rate of Interest

0% Processing Fees

No Hidden Charges

Car Loan

Minimum Documents.
Advance Payment Facility.
Car Loan Available Here Only.

Call Us
9828333666

वर्तमान विधानसभा सत्र में अधिकांश कार्य हो रहा पेपरलेस-देवनानी

तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के नवाचारों से विधानसभा को श्रेष्ठ बनाना लक्ष्य, उदयपुर प्रवास पर आए देवनानी ने मीडिया के साथ साझा किए नवाचारों के अनुभव

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के नवाचारों के माध्यम से राजस्थान विधानसभा को देश की एक श्रेष्ठ विधानसभा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में जारी विधानसभा सत्र के दौरान इन नवाचारों का सकारात्मक असर देखने को मिला है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि विधानसभा की सभी 200 सीटों पर आईपैड टेबलट लगाए गए हैं। सदस्यों को उनके उपयोग के बारे में विधिवत प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान सत्र का अधिकांश कार्य इन्हीं के माध्यम से ऑनलाइन किया जा रहा है। सदन में 12 टेक्नीशियन तैनात किए गए हैं जो सदस्यों को किसी भी प्रकार की तकनीकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। प्रयास किये जा रहे हैं कि सभी सदस्य ऑनलाइन कार्यप्रणाली में प्रवीण हो जाएं एवं पूरा सदन पेपरलेस तरीके से चलने लगे। अभी तक की प्रगति को देखते हुए अगले सत्र में विधानसभा के कार्य शत प्रतिशत पेपरलेस हो जाने की उम्मीद है। सर्किट हाउस में पूर्व उप महापौर पारस सिंघवी, समाजसेवी मांगीलाल जोशी, गजपाल सिंह, पुष्कर



तेली सहित कई गणमान्य लोगों ने विधानसभाध्यक्ष का स्वागत किया। देवनानी ने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था से सदस्यों को काफी सुविधा हो रही है एवं समय की बचत हो रही है। सदस्यों को अपने प्रश्नोंके ऑनलाइन उत्तर मिल जाने से वे सीधे ही पूरक प्रश्न कर रहे हैं इससे विधानसभा की

उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा सदस्यों को दो तीन दिन की बजाय उसी दिन शाम को कार्यवाही का फुटेज उपलब्ध करवाया जा रहा है।

देवनानी ने कहा कि इस बात के पूरे प्रयास किया जा रहे हैं कि विधानसभा सदस्यों द्वारा पटल

पर रखे गए सभी प्रश्नों के उत्तर समय पर मिल सकें। उच्चाधिकारियों को इस बात से अवगत कराने के पश्चात पूर्ववर्ती विधानसभाओं के अनुसरित पांच हजार प्रश्नों में से अब सिर्फ बारह सौ प्रश्नों के उत्तर आना बाकी रह गए हैं। पिछले बजट में पटल पर रखे गए दस हजार में से नौ हजार दो सौ पचास प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए जो कि लगभग 92 प्रतिशत हैं। जल्द ही यह आंकड़ा 95 तक पहुंच जाएगा। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एवं याचिका आदि के उत्तर भी प्राप्त होने लगे हैं।

देवनानी ने कहा कि विधानसभा अपनी परंपरा नियम एवं सिद्धांतों से चलेगी। इसके सुचारू संचालन के लिए सत्र से पूर्व सर्वदलीय बैठक के परिणाम भी सकारात्मक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों के तहत सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है जिससे जनता के मुद्दों को पूरी संवेदनशीलता के साथ पटल पर रखा जा रहा है। सदन में अनुशासन बनाए रखना अति महत्वपूर्ण है, अतः हल्के आचरण करने वाले सदस्यों पर पहले भी कड़ी कार्रवाई की गई थी और आगे भी ऐसा करने वालों को के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।



महाकुंभ प्रयागराज तीर्थ यात्रा करके लौटे गोस्वामी परिवार का स्वागत किया

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

रावतसर। ग्राम पंचायत रावतसर के प्रेमसागर गांव के गोस्वामी परिवार के बीस सदस्यों द्वारा महाकुंभ प्रयागराज त्रिवेणी संगम तट पर स्नान करके मंगलवार को वापस घर लौटने पर लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया और महिलाओं ने मंगलगीत गाकर आरती उतारी। प्रयागराज तीर्थ करने वाले में भंवर गिरी, मोहन गिरी, महेश गिरी, शेर गिरी, तेज गिरी, लिखम गिरी,मान गिरी, अचल गिरी, जवाहर गिरी,शिव गिरी, दीप गिरी, कुंभ गिरी, हीर गिरी ने संगम किनारे स्नान किया। सामाजिक कार्यकर्ता डालू जाखड़ ने बताया कि गोस्वामी परिवार ने मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ, पुष्कर, मेहंदीपुर बालाजी, खादूरश्यामजी सहित विभिन्न जगह का तीर्थ लाभ प्राप्त किया।



बाबा विश्वनाथ का लिया आशीर्वाद : काशी नगरी में श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाने के लिए लगी रही कतार

जागरूक जनता @ बसंत पंचमी के पावन अवसर पर वाराणसी में सोमवार को हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। दशधमैघ घाट पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, जहां स्नान कर लोगों ने पुण्य अर्जित किया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए विश्वनाथ धाम पहुंचे। भक्तों की कतारें गोदोलिया चौक मैदान तक फैली रहीं। मंदिर प्रशासन और पुलिस बल की दर्शन व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था रही।

किसान उत्पादक संगठनों की राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक का आयोजन



जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। केन्द्रीय परिवर्तित योजनागत एफपीओ गठन व संवर्धन के सम्बन्ध में सातवीं राज्यस्तरीय परामर्श समिति की बैठक शासन सचिव कृषि एवं उद्योगिकी राजन विशाल की अध्यक्षता में बुधवार को पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में आयोजित की गई। राजन विशाल ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों को और मजबूत कर किसानों के लिए उन्नत तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे कृषक उत्पादक संगठनों से किसानों को ज्यादा से ज्यादा

एनआईए को मिली 4 दुर्लभ आयुर्वेद सम्बन्धित पाण्डुलिपियों की प्रति



जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जयपुर। कई वर्षों पूर्व आमजन के बेहतर स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये लिखी गई प्राचीन पाण्डुलिपियों को आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा और शिक्षा में शोध के लिये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानक विश्वविद्यालय जयपुर का आयुर्वेद पाण्डुलिपि विभाग पूरे देश से मिलने वाली प्राचीन पाण्डुलिपियों और ग्रन्थों का संरक्षण कर रहा है। आयुर्वेद चिकित्सा में शिक्षा और शोध के लिए पाण्डुलिपि विभाग के दल को जैन ग्रन्थालय जयपुर से 4 दुर्लभ आयुर्वेद सम्बन्धित पाण्डुलिपियों की छाया प्रतियां लोकहितार्थ संरक्षण के लिये दी गईं। प्रो. अमित कुमार पांजा ने जानकारी देते हुए बताया पूज्य राष्ट्रीय सन्त आचार्य श्री विशालाचार जी की प्रेरणा से संस्थापित और पूज्य श्री प्रणय सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री समतल सागर जी महाराज के

होम्योपैथी महाविद्यालय, जोधपुर के छात्रों का दल शैक्षणिक भ्रमण के लिए हुआ रवाना



जागरूक जनता
jagrukjanta.net

जोधपुर। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के सघटक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के बी.एच.एम.एस. प्रथम वर्ष के 70 छात्रों का एक दल होम्योपैथिक दवा निर्माण कंपनी बैक्सन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, परवाणु (हिमाचल प्रदेश) के शैक्षणिक भ्रमण के लिए रवाना हुआ। यह भ्रमण कुलपति प्रोफेसर (वेद) प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को होम्योपैथिक औषधियों के मानकीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन तकनीकों एवं अनुसंधान प्रक्रियाओं की जानकारी देना है।होम्योपैथी कॉलेज के प्राचार्य डॉ. गौरव नागर ने बताया कि राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, नई दिल्ली के नियमानुसार बी.एच.एम.एस. प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए दवा निर्माण संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह औद्योगिक दौर छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक एवं औद्योगिक अनुभव प्रदान करेगा, जिससे वे बड़े पैमाने पर उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुसंधान में हो रहे नवाचारों को समझ सकेंगे। शैक्षणिक भ्रमण दल का नेतृत्व फार्मसी संकाय के विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव खन्ना कर रहे हैं। उनके साथ सहायक आचार्य डॉ. ऋषिकेश आचार्य, विभागाध्यक्ष (प्रसूति एवं स्त्री रोग) डॉ. आभा अग्रवाल, सहायक आचार्य (प्रेक्टिस ऑफ मेडिसिन) डॉ. धर्मेन्द्र कुमार भी साथ रहेंगे। यह भ्रमण 04 फरवरी से 08 फरवरी 2025 तक चलेगा, जिसमें छत्र फार्मास्यूटिकल उद्योग की आधुनिक तकनीकों, गुणवत्ता मानकों एवं उत्पादन प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेगे।

पौडित गौर्वंश को रेस्क्यू कर गौशाला पहुंचाया

जागरूक जनता @ गुड़मालानी। क्षेत्र के रामजी का गोल निकटवर्ती पिपारली ग्राम पंचायत के बलदेव नगर में युवाओं ने एक पौडित गौर्वंश को अपने सहयोग से गौशाला में पहुंचाया गया। युवा समाजसेवी अमेदाराम जांणी ने बताया कि पौडित गौर्वंश को चलना फिरना भी मुश्किल था काफी दिनों से खड़ी नहीं हो पा रही थी इसलिए आवार होने के कारण इलाज कराने वाला कोई नहीं था। ड्राइवर भाई आरुंराम थोरी ने अपने निजी वाहन में रेलवे स्टेशन गेट स्वागत, आवास व्यवस्था, सफाई, जल, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कर्मियों का गठन कर संस्थान साधकों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

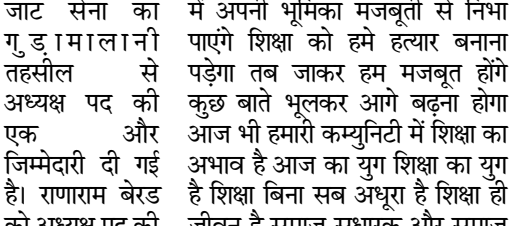
नारायण सेवा संस्थान का 43वां दिव्यांग सामूहिक विवाह की कमेडियां गठित

जागरूक जनता @ उदयपुर। नारायण सेवा संस्थान की ओर से 8-9 फरवरी को होने वाले 43वें निःशुल्क निर्वहन एवं दिव्यांग सामूहिक विवाह की तैयारियां जारों पर हैं। मंगलवार को संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। उन्होंने बताया कि उदयपुर जिले सहित संस्थान की सभी शाखाओं द्वारा जोड़ें का सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक 40 जोड़ों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा चुका है। कुछ जोड़ों का होना बाकी है। आज तैयारी मीटिंग में रेलवे स्टेशन गेट स्वागत, आवास व्यवस्था, सफाई, जल, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था कर्मियों का गठन कर संस्थान साधकों को जिम्मेदारियां सौंपी गईं।

श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का गुड़मालानी तहसील से राणाराम बेरड बने अध्यक्ष

जागरूक जनता
jagrukjanta.net

गुड़मालानी। क्षेत्र से राणाराम बेरड RLP मीडिया प्रभारी को श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का गुड़मालानी तहसील से अध्यक्ष पद की एक जिम्मेदारी दी गई है। राणाराम बेरड को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने पर लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाईयां देते हुए पूरा गुड़मालानी क्षेत्र खुशी जता रहे हैं पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है राणाराम बेरड को श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना का गुड़मालानी तहसील से अध्यक्ष बनाने पर राणाराम ने बताया अपन को समाज हित में काम करना है और



अपनी समाज में फैल रही कुरीतियों नशे पर बात करनी है अंकुश लगाना है और शिक्षा पर जोर देना है अगर हम शिक्षा पर गौर करेंगे तो शासन प्रशासन में अपनी भूमिका मजबूती से निभा पाएंगे शिक्षा को हमें हत्यार बनाना पड़ेगा तब जाकर हम मजबूत होंगे कुछ बातें भूलकर आगे बढ़ना होगा आज भी हमारी कम्युनिटी में शिक्षा का अभाव है आज का युग शिक्षा का युग है शिक्षा बिना सब अधूरा है शिक्षा ही जीवन है समाज सुधारक और समाज में जागरूकता लाने का पूरा प्रयास करूंगा। श्री राष्ट्रीय वीर जाट सेना टीम का हृदय की अटल गहराईयों से राणाराम बेरड ने धन्यवाद आभार व्यक्त करता किया आपने मेरे को जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा।

जागरूक जनता
www.jagrukjanta.net
विश्वसनीय समाचार पत्र

जी हाँ, यदि आपको अपने प्रतिष्ठान का व्यापार का विज्ञापन देना है तो जागरूक जनता समाचार पत्र द्वारा पूरे राजस्थान के साथ-साथ 4 अन्य राज्यों में आपका विज्ञापन प्रसारित किया जायेगा।

जो दिखेगा वही बिकेगा

आज ही बुक करें विज्ञापन

आपके व्यापार की तरक्की जागरूक जनता के साथ

विज्ञापन बुक करें: 9928022718 9829329070

विज्ञापन क्लासीफाइड डिस्प्ले प्रॉपर्टी तैवाहिक